



रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ (रेल दावा अधिकरण, पटना पीठ की सर्किट बेंच के तहत)
सुनवाई हाईब्रिड मोड के द्वारा सम्पन्न की गई।

दावा आवेदन संख्या - ओ.ए।।(यू)/पीएनबीई/25/2020



कोरम : श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक)

दावा पंजीकरण तिथि : 10.01.2020

निर्णय तिथि : 26.09.2025

1. बिनोद प्रसाद शॉ, पुत्र स्व० श्री सीताराम शॉ।

Binod Prasad Shaw Son of late Sitaram Shaw.

2. सोनिया देवी पत्नी बिनोद प्रसाद शॉ।

Sonia Devi Wife of Binod Prasad Shaw.

निवासीयान - मकान न० 25, छलता रोड, पी.ओ.- काकिनारा, पी.एस.- जगतडल,
जिला- 24 परगना नौब - 743126 (पश्चिम बंगाल)

.....प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के.गुप्ता द्वारा हाईब्रिड मोड।

प्रतिप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा हाईब्रिड मोड।

निर्णय

- माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, प्रधानपीठ दिल्ली महोदय के आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार उक्त प्रकरण को रेल दावा अधिकरण पटना पीठ के सर्किट

OAIU/PNBE/25/2020

बैच के तहत हाईब्रिड मोड पर सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में स्थानांतरण के तहत प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थीगण ने अपने पुत्र की अनापेक्षित दुर्घटना में चलती ट्रेन से नीचे गिर जाने के कारण कुल 10,00,000/- दस लाख रुपये मय 12 प्रतिशत ब्याज, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 संपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल किया है। दावा याचिका के परिशिष्ट में वर्णित प्रार्थीगण का प्रकरण निम्नानुसार है।



3. "1. That the deceased Vinay Kumar Shaw @ Vinay Shaw (unmarried), son of Binod Prasad Shaw, was traveling as a bonafide passenger having 2nd class traveling ticket No. URD60508530 dated 27.07.2019 from Gaya Jn. to Patna Jn. by Train 63254 Dn. Passenger train and in course of traveling, he fell down from the said running train near Makhdumpur Railway station and he became badly injured and thereafter he was brought to Sadar Hospital Jehanabad and thereafter he was referred to P.M.C.H., Patna for better treatment and in course of treatment he died at P.M.C.H., Patna on 28.07.19.

2. That on the basis of ferdbeyan of Anuj Kumar Rail P.S. Jehanabad U.D. Case No. 30/19 dated 07.08.2019 was registered and thereafter on completion of inquiry, the final report was submitted by the inquiry officer of the police station concern.

3. That the untoward incident was occurred under the zone of E.C. Railway, Hajipur.

4. That the police station of the deceased is Jagatdal but wrongly mentioned in the ferdbeyan of Anju Kumar as Bhatpara."

(Reproduced as Verbatim)

प्रार्थीगण ने अपने दावा याचिका के के समर्थन में मीमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव बालान, कर्द बयान अनुज कुमार, मर्ग रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, की प्रमाणित प्रति व सत्यप्रति मूल यात्रा टिकिट, मृतक व प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र की सत्यप्रति व बैंक पासबुक को दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रतिप्राप्ती ने अपना जवाबदाय नय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिप्राप्ती के द्वारा लिखित कथन की प्रारम्भिक आपत्तियों को पैरा सं० 2, 3, 4 व 5, का पुनरुत्पादन नीचे किया जा रहा है।



2. That the application has no cause of action to file this case against the respondent. Deceased was not a passenger or a bonafide passenger of the train.

3. That in reply to the statement made in Para 1 and 7 of the claim application contradicts the investigation DRM report that based on the observation of the documents complied and statement recorded it was found that:

a. That No ticket was recovered from the Possession deceased position which shows that he is not Bonafide passenger of the train. That the petition was filed by the applicant who has filed this case only to take compensation on the false ground that he is a Bonafide passenger.

b. the death review report has been made in presence of witness who were not eyewitness of the incident making it clear that no eyewitness was present during the incident.

c. The Train Driver stated that no person fell or cut during his duty.

d. Senior administrative engineer certified that the railway track was fully fit for operation between 61/10 to 61/12 on 27.07.2010.

4. That under no circumstances the respondent railway can be saddled with any liability and the applicant is not entitled to get any compensation.

5. That respondent further states that the untoward incident is not admitted. The allegation injury is not coming under the provision of section 123(c) of the railway act 1989. It is neither an accident nor an untoward incident for which claiming of

Signature

compensation under section 124A of railway act.

(Reproduced as Verbatim)

5. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 02.07.2021 को बनाए गये थे, उचित न्यायिक निराकरण हेतु वाद विषयों को पुनः निर्मित किया जा रहा है :



1. *Whether deceased was a bonafide passenger of train No. 63254 Down ?*
 2. *Whether death of the deceased is covered under section 123 (c) (2) of the Railway Act 1989.*
 3. *Whether applicant/dependents are dependents of the deceased?*
 4. *Whether applicant/dependents are entitled to receive compensation, if yes, to what extent?*
6. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी क्रमांक 01 ने स्वयं का शपथ पत्र (एडबल्यू -1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी से दिनांक 10.02.2023 को प्रतिपरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया की ओर से इस दावे के समर्थन में गीमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव चालान, फर्द बयान, मर्ग रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, मूल यात्रा टिकट, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, दस्तावेज सलग्न किये गये हैं।
7. प्रतिप्रार्थी के द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की गई डी.आर.एम. रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में अंकित कर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है।
8. प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में कथित किया है कि मृतक विनय साव उम्र करीब 26 वर्ष पे० विनोद प्रसाद साव, सा०- चलता रोड काकिनारा, था०- भाटपाड़ा, नॉर्थ चौबीस परगना (पश्चिम बंगाल) जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अपनी गलती पूर्वक किसी ट्रेन के चपेट में आ जाने से हुई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की

उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।

9. प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

वाद विषय 01 व 02



- सुविधा के दृष्टिकोण से एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो जिस कारण से वाद विषय क्रमांक 1 व 2 पर एक साथ विचारण किया जा रहा है।
10. दादा याचिका के अभिवचनों को प्रमाणित किये जाने बावत प्रार्थी क्रमांक 01 बिनोद प्रसाद शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र साक्षी एडव्यू-1 के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें उनके कथित किया कि मेरा पुत्र दिनांक 27.07.2019 को गया से पटना तक की यात्रा टिकिट लेकर पटना सवारी गाड़ी से यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान वह मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती गाड़ी से गिरकर बुरी तरह जखमी हो गया उसे ईलाज हेतु सदर अस्पताल, जहानाबाद भेजा गया जहां से पी. एम.सी.एच. पटना रेफर कर दिया गया एवं ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर अनुज कुमार जो मृतक ममेरा भाई है, सदर अस्पताल, जहानाबाद पहुँचे वहां से पी.एम.सी.एच. पटना आये, मृत्यु के बाद अपना कर्द बयान दिनांक 28.07.2019 को पी.एम.सी.एच., पटना में दिये जिसके आधार पर रेल बाना जहानाबाद के द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई। आरपीएफ, थाना जहानाबाद ने मुझे बयान देने जहानाबाद बुलाया था मैंने उनको कहा था कि मैं धाना नहीं आ सकता आप घर पर आकर बयान ले सकते हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि दिनांक 27.07.2019 को घटित घटना में मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी। मेरे पुत्र गया से पटना आ रहा था। वह अविवाहीत था। घटना की जानकारी मुझे मेरे साले के लड़के अनुज कुमार से हुई थी। मैं घटनास्थल पर नहीं गया था। टिकिट मेरे पुत्र के पास था जो जमा कर दिया है। मैंने अपने पुत्र को टिकिट कटवाते ट्रेन में चढ़ते ट्रेन से गिरते नहीं देखा था।
11. प्रतिप्रार्थी के द्वारा जवाबदाया एवं डीआरएम रिपोर्ट में कथित किया गया है कि मृतक किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था, नाही उसके पास कोई रेल टिकिट



पाया गया। मृतक की मृत्यु अपनी गलतीपूर्वक किसी ट्रेन की चपेट में आ जाने से हुई है। घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) में परिभाषित अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है। रेल प्रशासन कोई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी करने हेतु उत्तरदायी नहीं है। प्रतिप्राची के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किये जाने बावत किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं करवाया गया है।

13. प्राचीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उप स्टेशन मास्टर, मखदुमपुर, गया का मेमो दिनांक 27.07.2019 प्रस्तुत किया है जिसमें कथित किया गया है कि अनी 63254 डाउन पैसेन्जर ट्रेन से एक आदमी गिर गया है। जिसका पैर पुरी तरह से जखमी हो गया है। अतः उचित उपचार के लिये आपके यहां भेज रहे हैं। घटना की सूचना पर मृतक दिनय शॉ के परिजन अस्पताल पहुँचे व ईलाज के क्रम में मृत्यु होने के पश्चात मृतक के ममेरे भाई अनुज कुमार द्वारा एक लिखित आवेदन रेल थाना, जहानाबाद को दिया गया जिसके आधार पर यूडी प्रकरण क्रमांक 30/2019 दर्ज किया गया। आवेदन पत्र में लेख है कि मेरे भाई दिनय दिनांक 27.07.2019 को रेल यात्रा टिकट गया से पटना लेकर मेमो ट्रेन से गया से पटना की यात्रा ट्रेन 63254 में कर रहा था। जिसका यात्रा टिकट नम्बर यूआरडी 60508530 है। यात्रा के दौरान भीड़ के कारण मेरा भाई मखदुमपुर स्टेशन पर गिर गया। जीआरपी, जहानाबाद के द्वारा अनुवेक्षण के दौरान पीएमसीएच पटना में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई जिसमें पंचों के द्वारा राय दी गई है कि चलती ट्रेन से गिरकर जखमी होने के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु घोषित किया गया। जीआरपी, जहानाबाद ने अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन में मृतक का यात्रा टिकट कथ्य कर यात्रा करना एवं यात्रा के दौरान गाड़ी सं 63254 डाउन से गिरने के कारण जखमी होने एवं ईलाज के दौरान मृत्यु होना कथित किया है। मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर फटे हुये घाव पाये गये एवं मृत्यु का कारण रक्तस्राव एवं अघात दर्शाया गया है। डीआरएम रिपोर्ट के साथ सलंग्न स्टेशन हाथरी में उल्लेख है कि गाड़ी सं 63254 डाउन पैसेन्जर से एक अज्ञात पैसेन्जर गिर गया जिसको मखदुमपुर, राजकीय अस्पताल भेजा।

14. एडव्यू 01 मृतक के पिता विनोद प्रसाद शॉ ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि दिनांक 27.07.2019 को मेरा पुत्र गया से पटना तक का यात्रा टिकट लेकर सवारी गाड़ी से यात्रा कर रहा था। प्रतिपरीक्षण ने साक्षी ने कथित किया है कि जो टिकट बेटे के साथ था उसे आवेदन के साथ जमा कर दिया है। इसके

Sum



अतिरिक्त यात्रा टिकिट के बिन्दु पर अन्य कोई प्रतिपक्षिण नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मूल यात्रा टिकिट प्रस्तुत किया गया है जिसका सत्यापन कराये जाने पर मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, ई.सी.रे. गया अपनी रिपोर्ट में टिकिट जारी किया जाना स्वीकार किया गया है। टिकिट का उल्लेख मृतक के चचेरे भाई अनुज कुमार ने जीआरपी को दिये गये आवेदन पत्र में भी लेख किया है इसके अतिरिक्त अंतिम जांच प्रतिवेदन में भी जीआरपी ने कथित किया है कि मृतक यात्रा टिकिट लेकर यात्रा कर रहा था। अतएव मृतक के सदभावी यात्री होने के संबंध में कोई संदेह नहीं है।

15. साक्षी बिनोद प्रसाद शर्मा ने अपने शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि मृतक यात्रा के दौरान मखदुमपुर रेलवे स्टेशन पर गिरकर जखमी हो गया, पहले उसे सदर अस्पताल, जहानाबाद भेजा गया जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया एवं ईलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी की शपथ पत्रिय साक्ष्य पर संदेह किये जाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि साक्षी का कथन स्टेशन अधीक्षक, मखदुमपुर के मेमो एवं स्टेशन डायरी में लेख किये गये तथ्यों से समर्थित है इसके अतिरिक्त जीआरपी के द्वारा भी अनुवेक्षण में मृतक का यात्रा के दौरान गाड़ी सं० 63254 डाउन से गिरकर जखमी होना व ईलाज के दौरान पीएमसीएच, पटना में मृत्यु होना कथित किया है।

इस संकेत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar, (2008) 9 SCC 527** में निर्धारित किया है कि :-

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or

welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दों के यदि दो अर्थ निकलते हैं तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उद्देश्य हेतु उक्त विधान को निर्मित किया गया है एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उद्देश्य सफल हो सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के मामले में निर्धारित किया है कि

".....Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de- boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

प्रतिप्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथित किया कि मृतक स्वयं के अपराधिक कृत्य एवं स्वयं को पहुँचाई गई क्षति के कारण मिरकर घायल हुआ एवं ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिस कारण रेलवे प्रशासन, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 (क) में उल्लेखित अपवाद (ख) एवं (ग) के तहत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के उत्तरदायी नहीं है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 124 (क) के अपवाद (ख) "स्वयं को पहुँचाई गई क्षति" के संबंध में निर्धारित किया है कि :-

".....the concept of "self-inflicted injury" would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree. Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on "no fault theory". We may in this connection refer to the judgment of this Court in *United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar* [*United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar*, (2019) 12 SCC 398; 2017 SCC OnLine SC 1443; (2017) 13 Scale 652] laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on "no fault theory" under Section 163-A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an "untoward incident" entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124-A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह भी निर्धारित किया है कि :-



".....In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."

उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टान्त से स्पष्ट है कि "स्वयं को पहुंचाई गई क्षति" व "स्वयं का अपराधिक कृत्य" को प्रमाणित किये जाने बावत मृतक का आशय अथवा अपराधिक दुराशय प्रमाणित किया जाना आवश्यक है परंतु प्रतिप्राप्ती के द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घटना में मृतक का स्वयं को क्षति पहुंचाने का कोई आशय अथवा अपराधिक दुराशय रहा है एवं घटना धारा 124 (ए) के अपवादों में आती है।

उपरोक्त वर्णित मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टान्त के आधार पर मैं यह निर्धारित करता हूँ कि मृतक घटना दिनांक 27.07.2019 को गाडी सं० 63254 डाउन में सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान मखदुमपुर स्टेशन पर गिरकर घायल हुआ एवं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अतएव मृतक घटना के समय धारा 2 (29) रेलवे अधिनियम में परिभाषित अनुसार सदभावी यात्री था व कथित घटना धारा 123 (सी) (2) व 124 ए रेलवे अधिनियम के तहत अनापेक्षित घटना की श्रेणी में आती है, जो उक्त धारा उल्लेखित अपवादों की श्रेणी की नहीं है। अतएव बाद विषय क्रमांक 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष व प्रतिप्राप्ती रेलवे प्रशासन के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

बाद विषय : 03

16. प्रार्थीगण मृतक के माता पिता हैं उक्त आशय के कथन प्रार्थी ने अपनी शपथ पत्रिका साक्ष्य में कथित किया है एवं दावा याचिका के लगबग रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं को मृतक पर आश्रित होना नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मृतक का आधार कार्ड, वोटर आई.डी कार्ड, प्रार्थीगण का आधार कार्ड, एवं भरतपुर निगम के पार्श्व के द्वारा जारी परिवारिक सूची प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण मृतक के माता पिता हैं एवं मृतक पर घटना के

Swing

समय आश्रित रहे है। अतएव वाद विषय क्रमांक 03 उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

वाद संख्या 04



17. मृतक घटना दिनांक को सदस्यी यात्री के नाते गाडी सं0 63254 डाउन से यात्रा के दौरान मखदुमपुर स्टेशन पर अनापेक्षित घटना में ट्रेन से गिरने पर आई चोट से ईलाज के दौरान मृत हो गया जिस कारण से मृतक के उपरोक्त समस्त आश्रित रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि रुपये 8,00,000/- रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के पार्ट एक में उल्लेखित अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी है। मृतक के उपरोक्त आश्रित क्षतिपूर्ति राशि रुपये 8,00,000/- पर घटना दिनांक 27.07.2019 से अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय क्रमांक 04 निर्णित किया जाता है।

आदेश

ORDER

18. यह दावा प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थीगण को रु 8,00,000/- (रु आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को घटना दिनांक 27.07.2019 से मुआवजा राशि के अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है।

प्रार्थीगण का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एग्युटी / सावधि राशि
श्रीमोद प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व० श्री सीताराम शर्मा। Binod Prasad Sharm Son of late Sitaram Sharma.	रु 4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र)	रु 40,000/- (चाहीस हजार रुपये मात्र) अनुपातिक ब्याज	रु 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक में सावधि में जमा रखा जाएगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थी को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।



सोनिया देवी पत्नी विनोद प्रसाद शर्मा। Sonia Devi Wife of Binod Prasad Sharma.	रु 4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र)	रु 40,000/- (चाहीस हजार रुपये मात्र) आनुयायिक व्याज	रु 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक में संचयि में जमा रखा जावेगा। इस संचयि पर मिलने वाले मासिक व्याज की राशि प्राथमिक को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।
--	---	---	--

- प्रतिप्राथी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि यह व्याज सहित मुआवजा राशि को
अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण के सूटर मनी (Suitor Money)
एकॉउंट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट
किया जाता है कि प्रतिप्राथी रेलवे व्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते
समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यूटीआर नंबर, व्याज की गणना सहित
आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदक को देगा
एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।
19. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ
(एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में
माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया
गया :-

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been

ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in *Krishnamurthi v New India Insurance Company*, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."



20. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है-

"5. Mode of Payment-

- 5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.
- 5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.
- 5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursement for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.
- 5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in *Geeta Devi Vs Union of India*, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

Sum



21. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण धरण क्रमांक 18 में उल्लेखित अनुसार किया जावे।
22. प्राथीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।
23. यदि प्राथीगण टीडीएस कटौती की धूल का हकदार है तो वह फार्म-15जी या फार्म-15-एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।
24. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाये—
1. प्राथीगण के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।
 2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्राथीगण की सावधि जमा कर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।
 3. बैंक प्राथीगण को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।
 4. बैंक प्राथीगण की पारसबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्राथीगण को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किये गये हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किये जायेगा। प्राथीगण उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पारसबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

Swir

25 उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 26.09.2025 को अधिष्ठापित किया गया।



(राजीव जैन)

सदस्य (न्यायिक)

रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ
पटना पीठ की सर्किट बैच के तहत